सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607,
तिरुवनंतपुरम - 695 039
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. NO. 5607
THIRUVANANTHAPURAM - 695 039

सं/ No. .....

दिनांक / Date :.....

P19/II/DRSSA-62/RJ/2018-19 **19/07/2018**

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Grant of interim Relief on pension to the Retired Judicial Officers of the Government of Rajasthan and their family Pensioners wef 01/01/2016-reg

Ref: 1. No. Pension Auth./Order./K-85/2018-19/1124 dated 13.06.2018 received from the O/o Accountant General (A&E), Rajasthan
2. F. No. 10(5)/law/2018 Jaipur, dated 21/05/2018 received from the law & Legal Affairs department, government of Rajasthan

I am to enclose herewith copy of SSA received from the office of Accountant General (A&E), Rajasthan regarding the grant of interim Relief to the Retired Judicial Officers of the Government of Rajasthan and their family Pensioners wef 01/01/2016. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link "*Treasury endorsement of orders for other state pensioners*". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

दूरभाष / Telephone: 0471 - 2330311 फैक्स / Fax : 0471 - 2330242 तार / Grams: ACCOUNTS TRIVANDRUM
इ-मेल / E-mail : agaekerala@dataone.in Website : http://www.agker.cag.gov.in

PM/2/224/2018-19. (6)

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड-पत्र

Pm/13/DRSSA/62 2016
02/7/18

221 6/1/8.

संख्या / No. पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/2018-19/ 1124

PM

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 13/6/18

114417
19/6/18

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़),
केरल, एम.जी. रोड,
पो. बॉ. नं. 5607
तिरुवनंतपुरम -695039

विषय:- राजस्थान न्यायिक सेवा से सेवानिवृत अधिकारीयों की पेंशन व पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन पर अंतरिम राहत के भुगतान बाबत |

प्रसंग:- राज्य सरकार के विधि एवं विधिक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (5)/विधि/2018 दिनांक 21.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(247)निपेवि/नियम/2018/पार्ट-2/1707-1770 H दिनांक 30.05.2018 एवं राज्य सरकार के विधि एवं विधिक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (5)/विधि/2018 दिनांक 21.05.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे |

सलंग्र:- ज्ञापन दिनांक 21.05.2018 की प्रति (2)

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

क्रमांक:- पीए/आदेश/2018-19 दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर |
(2) प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), जयपुर |
(3) शाखाधिकारी, टी.एम. अनुभाग |

To
P/S for n.a
2/7/18

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन प्राधिकृति

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

Government of Rajasthan

Law & Legal Affairs Department

10(5)/Law/2018 Jaipur, Dated 21 MAY 2018

ORDER

The Governor is pleased to order to implement the following recommendations of the Second National Judicial Pay Commission:-

"1. Interim relief to the extent of 30% of increase in basic pay with accrued increments shall be paid to all categories/ranks of Judicial Officers.
2. The said increased in Pay shall be treated as a separate component and no D.A. is payable thereon.
3. Arrears shall be worked out with effect from 01.01.2016 on the above basis. The details of calculations are set out in Annexure-I.
4. On the same basis, the interim relief shall be provided to the pensioners and family pensioners with effect from 01.01.2016 and the arrears to be paid accordingly subject to the condition that if pension/family pension of judicial officers has been revised under FD Memorandum No. F.12(6)FD/Rules/2017 dated 30.10.2017 and 09.12.2017 that amount of increase in pension/family pension alongwith dearness relief thereon shall be adjusted against the amount of interim relief payable under this order.
5. The amounts payable by way of interim relief under this order are liable to the adjusted against the future determination pursuant to the final report submitted by the Commission."

This order issues with the concurrence & Vetting of Finance(Rules) Department vide their I.D. No. 101802095 dated 30.04.2018 & 101802730 dated 21.05.2018 Respectively.

By order of the Governor.

Sd/-
(Mahaveer Prasad Sharma)
Principal Secretary, Law

Copy forwarded for information and necessary action:-

1. Secretary to the Hon'ble Governor of Rajasthan.
2. Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister of Rajasthan.
3. P.P.S. to Chief Justice of Hon'ble High Court, Jodhpur.
4. P.S. to Hon'ble State Law Minister of Rajasthan.
5. P.S. to Hon'ble Chief Secretary, of Rajasthan.
6. Registrar General, Hon'ble High Court, Jodhpur/Jaipur Bench Jaipur.
7. P.S. to Principal Secretary, Law
8. Principal Accountant General, Rajasthan Jaipur.
9. Principal Accountant General(Audit), Rajasthan Jaipur.
10. P.S. to A.C.S. Finance (Rules/budget) of Rajasthan.
11. Director, Pension and Pension Welfare, Rajasthan, jaipur.

21.5.18
Joint Secretary, Law

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–प05 (247)/निपेवि/नियम./2018/पार्ट–2/1707-1770 H. दिनांक 30-05-2018

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर
2. समस्त कोषाधिकारी,————————,राजस्थान
3. पेंशन वितरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत समस्त बैंक

विषय :–राजस्थान न्यायिक सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों की पेंशन व पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन पर अंतरिम राहत के भुगतान बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के विधि एवं विधिक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (5)विधि/2018 दिनांक 21.05.2018 के द्वारा राजस्थान राज्य के न्यायिक सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर उनकी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रति माह दिनांक 01.01.2016 से देने हेतु निर्देश जारी किये है (प्रति संलग्न) । राज्य सरकार के उक्त आदेशों कि अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों व पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन का भुगतान **01.01.2016 से अथवा जिस दिवस से पेंशन प्रारम्भ हुई हो (जो भी बाद में हो से)** निम्नांकित शर्तो के अनुसार भुगतान करने की कार्यवाही करने की व्यवस्था करें:–

(1) उक्त अंतरिम राहत पर किसी भी प्रकार की मंहगाई राहत देय नहीं होगी ।

(2) अगर किसी भी सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी व पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार के वित्त विभाग(नियम) द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 या 9.12.2017 के अनुसार सांतवे वेतनमान के अधीन कोई पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण कर लाभ दिया गया है व उस पर मंहगाई राहत दे दी गयी है, तो उक्त पूर्व में किये गये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण को निरस्त कर पूर्व में किये गये अधिक भुगतान की राशि को उक्त अंतरिम राहत में से समायोजित किया जाना है ।

(3)उक्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से अंतरिम राहत की गणना कर माह जून, 2018 में देय पेंशन के साथ बकाया मासिक अंतरिम राहत का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें । जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना हो सकें ।

(4) उक्त भुगतान की गयी अंतरिम राहत की राशि को दर्शाने हेतु न्यायिक अधिकारियों के पेंशन के स्कॉल में, उचित प्रावधान सॉफ्टवेयर में कर दिया गया हैं। सभी बैंकर्स व कोषालयों से अनुरोध है कि अंतरिम राहत के भुगतान की राशि को स्कॉल में अलग से दर्शाये व कितने समय की दी गयी है, इंगित करें ।

(5) जून 2018 के बाद नियमित रूप से अग्रिम आदेशों तक न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम राहत भुगतान सुनिश्चित किया जावे तथा भविष्य में जब भी सरकार के द्वारा न्यायिक अधिकारियो हेतु वेतनमान की घोषणा की जावेगी उसमें से अंतरिम राहत के रूप में किये गये भुगतान को समायोजित किया जाना है ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) Office of the Account General प्राप्ती संख्या/Receipt
01 JUN 2018
2117
राजस्थान, जयपुर Rajasthan

भवदीय,

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

Under Special Seal Authority
Registered Post

No. Pension Auth./Order/K-85/2018-19/1124

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

Date 13.06.18

To

The Accountant General (A&E) Kerala
M.G Road,
P.O Box no. 5607
Thiruvananthapuram -695039

Sub :- Payment of interim relief on pension to the pensioners retired from Rajasthan Judicial Services and on the pension of family pensioners- reg.

Ref :- Order no. F 10(5)/Law/2018 dated 21.05.2018 of Department of Law and Legal Affairs of State Government.

Sir,

On the above subject, it is stated that copy of letter no. P5(247)DPD/Rules/2018/Part-2/1707-1770 H dated 30.05.2018 of the Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur and Order no. F 10(5)/Law/2018 dated 21.05.2018 of Department of Law and Legal Affairs of State Government are being forwarded for necessary action.

Hence, you are requested to circulate the above orders to all Treasury Officers/ Pension Payment Officers/Branches of Banks under your jurisdiction and direct them for making payment and forward a copy to this office as well.

Encl:- Copy of Memo dated 21.05.2018

Yours Faithfully,
Sd/-
Sr Accounts Officer/ Pension Authority

URGENT

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR

Sl No. P 05 (247)/DPD/Rule/2018/Part-2/1707-1770 H Dated 30.05.2018

1. The Accountant (A&E), Rajasthan, Jaipur
2. All Treasury Officers, ..., Rajasthan
3. All Banks Authorised by the Government of Rajasthan for Disbursement of Pension

.....

Sub : Payment of interim relief on the pension of the officers retired from Rajasthan Judicial Services and on the pension of family pensioners- reg.

Sir,

On the above mentioned subject, directions have been issued for grant of interim relief @30% per month w.e.f. 01.01.2016 on the pension of the retired officials of Rajasthan State Judicial Service and on the basic pension/family pension of family pensioners vide Order No. F 10(5) Law/ 2018 dated 21.05.2018 of the Law & Legal Affairs Department of the State Government (copy attached). To ensure compliance of the above orders of the State Government, arrangements may please be made for taking action for payment of interim relief @30% per month **w.e.f. 01.01.2016 or from the date of commencement of pension (whichever is later)** on the pension of the retired officials of Rajasthan State Judicial Service and on the basic pension/family pension of family pensioners, as per the following terms :

1. Dearness relief of any kind shall not be payable on the above interim relief.

2. If any retired Judicial Officer or family pensioner has been given the benefit of fixation of pension/family pension under the Seventh Pay Commission as per the Order/Circular/ Notification dated 30.10.2017 or 9.12.2017 issued by the Finance (Rules) Department of the State Government and dearness relief has been granted on it, the fixation of pension/family pension done earlier may be cancelled and the amount of excess payment made earlier may be adjusted from the above interim relief.

3. Kindly ensure payment of outstanding monthly interim relief to the above officials, along with the pension payable in the month of June, 2018 after calculating the interim relief from 01.01.2016 so as to comply with the decision of the Supreme Court.

4. For showing the payment of the amount of above interim relief, necessary provisions have been done in software in the pension scroll of the judicial officers . All the bankers & treasuries are requested that the amount of payment of interim relief may be shown separately in the scroll and mention the time for which it has been paid.

5. After June 2018, till further orders, the regular payment of interim relief to the judicial officers may be ensured and in future whenever any declaration regarding pay scales of judicial officers would be made, the payment made as interim relief is to be adjusted from the same.

Kindly give top priority to this.

Encl : as above

Yours faithfully,
Sd/-
(Parmeshwari Choudhary)
Director